

धक,

संख्या- /X-2-2014-12(31)/2014

मनोज चन्दन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

।वा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

न एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 13 अगस्त, 2014

विषय:- वन विभाग के अनुदान सं०-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आयोजनागत पक्ष की बाह्य सहायतित योजना "उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जाइका वित्त पोषित) (राजस्व पक्ष)" में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

होदय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 की आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-318/XXVII(1)/2014 दि० 18 मार्च, 2014 में दिये गये निर्देशों के आलोक में एवं उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन व वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के प०सं० नि०-2017/3-6(30व०सं०प्र० परियोजना), दि० 21 जून, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश आ है कि वन विभाग के आयोजनागत पक्ष की योजना "उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जाइका वित्त पोषित) (राजस्व पक्ष)" में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष ₹ 10,50,00,000/- (₹ दस करोड़ पचास लाख मात्र) धनराशि व्यय आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-318/XXVII(1)/2014 दि० 18 मार्च, 2014 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदों में व्यय किया जाय।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
4. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. आपके निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी०एम०-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
8. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
9. आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय बनाविकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10. संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय शासन को सूचित किया जाय।
11. स्वीकृति कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि धनराशि की बचत होती है तो बचत की धनराशि यथासमय शासन को सूचित की जाय।
12. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
13. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
14. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1408270045 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
15. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-638/XXX-1-12(25)2011, दि० 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 102 समाज तथा फार्म वानिकी 97-01 उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जाइका वित्त पोषित) हेतु हेतु निम्नलिखित सूची में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

(धनराशि हजार में)

क्र० सं०	योजना का नाम/लेखा शीर्षक/मानक मद		आय-व्ययक प्रावधान (प्रथम अनुपूरक सहित)	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति
1	2406-	वानिकी तथा वन्य जीवन		
	01-	वानिकी		
	102-	समाज तथा फार्म वानिकी		
	97-01-	उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जाइका वित्त पोषित)''		
	20-	सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता	50000	50000
	43-	अन्य व्यय	550000	550000
	योग		105000	105000

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ दस करोड़ पचास लाख मात्र)

3- ये आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 44(P)/XXVII-4-14 दि० 08 अगस्त, 2014 के आलोक में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

क्रमशः.....3

1610(A)
ख्या- /X-2-2014, तददिनांकित.

तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ✓ 12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

(मनाजि चन्दन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Forest (S016)

1610(A)
पत्र संख्या - IX-2-2014-12(31)/2014

पत्र संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1408270045

आवंटन पत्र दिनांक -11-Aug-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

देखा शीर्षक 2406 - बानिकी तथा वन्य जीवन
102 - समाज तथा फार्म बानिकी
01 -

01 - बानिकी

97 - बानिकी परियोजना (विश्व बैंक पोषित)

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Plan Voted
			योग
20 - सहायक वनवान/बंशदान/राज	0	50000000	50000000
43 - बेतन भरे ज़ादि के लिये सहाय	0	55000000	55000000
	0	105000000	105000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

105000000